झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

दोषमुक्ति अपील (खंडपीठ) संख्या 40/2023

(30.06.2022 को सत्र विचारण संख्या 56/2021 एवं एस. टी. संख्या 57A/21 और एस. टी. संख्या 167/2022) मामले में माननीय ए.डी.जे, प्रथम, गोड्डा द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध)

झारखंड राज्य धीरज प्रकाश के माध्यम से, पिता बी. एल. अग्रवाल, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी बोरिजोर, डाकघर और थाना बोरिजोर, जिला-गोड्डा, झारखंड। (उपायुक्त, गोड्डा द्वारा बरी करने की अपील दायर करने के लिए अधिकृत, पत्र संख्या 381/कानूनी दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. अन्नू सिंह उर्फ अन्नू के. सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता मोहन सिंह, निवासी गाँव-पुन्सिया, डाकघर गोड्डा कॉलेज, थाना गोड्डा (टाउन) जिला गोड्डा, झारखंड।
2. सोनू झा, आयु लगभग 38 वर्ष, पिता सिद्धनाथ झा, निवासी गाँव-गुलजारबाग गोड्डा, डाकघर गोड्डा, थाना गोड्डा (टाउन) जिला गोड्डा, झारखंड
3. सौरभ कुमार चौधरी उर्फ चीकू चौधरी, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता स्व. पूरन चोधरी, निवासी गाँव-मोतीया, डाकघर मोतीया, थाना मोतीया (ओ.पी.) जिला गोड्डा, झारखंड।
4. अमित कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता श्री भगवान प्रसाद तिवारी, निवासी गाँव-सरदार पटेल नगर, डाकघर गोड्डा, थाना गोड्डा (टाउन) जिला गोड्डा, झारखंड
5. अभय कुमार, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी गाँव-भारतखंड,पिता स्वर्गीय चंद्र शेखर मिश्रा, डाकघर बिशुनपुर, थाना परबत्ता जिला खगड़िया (बिहार)
6. पप्पु झा उर्फ राजीव रंजन झा, आयु लगभग 48 वर्ष, पिता स्वर्गीय उदयकांत झा, ग्राम-पासोहोन, डाकघर धोरैया, थाना धोरैया, जिला बांका (बिहार)

... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायधीश श्री सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय न्यायधीश श्री नवनीत कुमार

याचिकाकर्ता के लिएः श्री प्रिय श्रेष्ठ, विशेष लोक अभियोजक
उत्तरदाता के लिए: श्री पुर्णेन्दु कुमार झा, अधिवक्ता

10/19 दिसंबर 2023

अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 4220/2023:

1. आई.ए संख्या 4220/2023 में झारखंड राज्य द्वारा 30.06.2022 को पारित सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, गोड्डा द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील के लिए दाखिल की गई है, जो एस.टी. मामला संख्या 56/2021 और एस.टी. मामला संख्या 57ए/2021 तथा एस.टी. मामला संख्या 167/2022 (एस.टी. मामला संख्या 57ए/2021 और एस.टी. मामला संख्या 167/2022 का परीक्षण एकीकृत किया गया) से संबंधित है।

2. इसे ध्यान में रखते हुए, आई.ए संख्या 4220/2023 स्वीकृत है।

<u>दोषमुक्ति अपील (खंडपीठ) संख्या 40/2023</u>

3. तत्काल बरी करने की अपील राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के अंतर्गत दाखिल की गई है, जो 30.06.2022 को पारित सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, गोड्डा द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील के लिए दाखिल की गई है, जो एस.टी. मामला संख्या 56/2021 और एस.टी. मामला संख्या 57ए/2021 तथा एस.टी. मामला संख्या 167/2022 (एस.टी. मामला संख्या 57ए/2021 और एस.टी. मामला संख्या 167/2022 का परीक्षण एकीकृत किया गया)। इस निर्णय में यह पाया गया कि प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सभी संदेहों से परे सिद्ध नहीं हुए हैं, और इस प्रकार आरोपी व्यक्ति, जो यहाँ प्रतिवादी हैं, को बरी कर दिया गया है।

4. लिखित बयान के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं -

सूचनार्थी- दिनेश सिंह, अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के साथ साझेदारी के आधार पर सड़क परियोजनाओं में काम करते हैं। 06.08.2019 को, अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने अपने मोबाइल नंबर 7004872800 से उन्हें लगभग दोपहर 12 बजे अपने घर, विक्रमशिला, बुलाया। इसके बाद, सूचनार्थी अशोक तिवारी के घर गया, जहाँ वह लगभग 1:00 बजे पहुँचा। जैसे ही सूचनार्थी अशोक तिवारी के घर पहुँचा, उसने सूचनार्थी से पूछा कि उसने 2 करोड़ रुपये कहाँ रखे हैं। जब सूचनार्थी ने बताया कि उसके पास वह पैसा नहीं है, तो अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने उसे हत्या की धमकी दी। इसके बाद अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने सूचनार्थी पर पिस्तौल के बट से हमला करना शुरू कर दिया। अन्य आरोपी व्यक्ति जैसे चीकू चौधरी, सोनू चौधरी, अन्नू सिंह, राहुल साह और अमित तिवारी उर्फ बाबू तिवारी, जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी सूचनार्थी का गला दबाना शुरू कर दिया ताकि उसकी हत्या की जा सके। गला दबाने के परिणामस्वरूप, सूचना देने वाले का नाक और मुँह से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। आगे आरोप लगाया गया है कि उसे बेरहमी से पीटा गया, यहाँ तक कि जब वह बेहोश था और जब उसे होश आया, तो उसे फिर से पीटा गया, जिससे उसकी बाईं आँख घायल हो गई। इसके बाद, आरोपियों ने उसे बांध दिया और बार-बार उससे 2 करोड़ रुपये देने को कहा, जो कहा जाता है कि उसके पास रखे गए थे। इस बीच, अभय कुमार, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, साहेबगंज को फोन पर बुलाया गया कि सूचनार्थी को पकड़ लिया गया है। दो घंटे बाद, प्रबंधक अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के घर आया और सभी व्यक्तियों ने उसे पूरी रात प्रताड़ित किया और पूछा कि पैसे कहाँ रखे हैं। आरोपियों ने उसे धमकी दी कि यदि वह नहीं बताएगा कि पैसे कहाँ रखे हैं, तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। इसके अलावा, पूरी रात उसे प्रताड़ित करने के बाद, शाखा प्रबंधक अभय कुमार ने साहेबगंज जाने के समय उसे धमकी दी कि उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा। उक्त शाखा प्रबंधक ने सूचनार्थी के हस्ताक्षर जबरदस्ती लेने के बाद अपनी कार में रखी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की सभी चेकबुकें ले लीं। उसने आगे आरोप लगाया कि उक्त शाखा प्रबंधक अपने साथ मशीनों के सभी बिल भी ले गया और सुबह, अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने उसके चेहरे पर तौलिया बांधकर उसे अपने बोलेरो में पसाना, पप्पू झा के घर ले गया।

इसके आगे आरोप लगाया गया है कि पप्पू झा के घर पर, अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने सूचनार्थी की बेटी, जिसका नाम अंकिता है, को फोन किया। इसके बाद, सूचनार्थी की पत्नी, जूली को अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने बुलाया और फिरौती के रूप में 50 लाख रुपये की मांग की। उक्त बातचीत का रिकॉर्ड सूचनार्थी के पास उपलब्ध है। सूचनार्थी ने आगे आरोप लगाया कि आरोपियों ने धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए, तो उसकी हत्या कर दी जाएगी और इसके बाद, सूचनार्थी को 07.08.2019 को रात लगभग 8:00 बजे गोड्डा में मुक्त किया गया। उसने आगे आरोप लगाया कि अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना

तिवारी ने अपनी बोलेरो (जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH-01-BG-8201 है) अपने पास रखी हुई थी। उसने यह भी कहा कि उसने 05.08.2019 को अपने ड्राइवर, संतोष कुमार को 7,000/- रुपये का अंतिम चेक जारी किया और इसके बाद उसने किसी को भी कोई चेक नहीं दिया। उसने आगे आरोप लगाया कि अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की धमकी के कारण वह पिछले एक महीने से बाहर नहीं गया और अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के सहयोगी लगातार उस पर नजर रखे हुए थे और उसकी हत्या कभी भी की जा सकती थी। उसने आगे आरोप लगाया कि 05.09.19 से 09.09.2019 के बीच, अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी अपने 5-6 लोगों के साथ उसके घर के पास आया, जिससे सूचनार्थी डर के मारे अपने घर में छिप गया और पिछले एक महीने से अपने घर से बाहर नहीं आया। इसके बाद, उसे अपने स्टाफ से पता चला कि उसकी सभी मशीनें अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी द्वारा रात 12 बजे जबरदस्ती ले ली गई हैं, तब उसने पुलिस के समक्ष लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।

5. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, गोड्डा (टाउन) थाना मामला संख्या 235/2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 364ए, 365, 386, 379 और 307 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई।

6. जांच के बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की और मामला सत्र न्यायालय में भेजा गया, जहाँ आरोपियों ने दोषी नहीं /निर्दोष होने का अनुरोध किया और मुकदमे की मांग की। इसके अनुसार, मुकदमा शुरू हो गया है।

7. विद्वान न्यायालय ने पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रतिकूल तर्कों का मूल्यांकन करते हुए, साथ ही पक्षों की ओर से पेश की गई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करते हुए, यह पाया कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा है। न्यायालय ने आरोपियों (यहाँ प्रतिवादी) को आरोपों से निर्दोष पाया और इस प्रकार, उन्हें उन आरोपों से बरी कर दिया, जो वर्तमान अपील का विषय है।

8. अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बरी करने के फैसले पर सवाल उठाया है और कहा है कि निचली अदालत ने साक्ष्यों को सही दृष्टिकोण से नहीं समझा और न ही अपने न्यायिक मन को लागू किया। केवल पी.डब्ल्यू.-6, जांच अधिकारी उपेंद्र सिंह के बयान की गलत व्याख्या के आधार पर उसने आदेश पारित किया और जांच एजेंसी पर प्रतिकूल टिप्पणी की|

9. इसके अलावा, निचली अदालत ने यह भी समझने में असफलता दिखाई है कि प्रतिवादियों के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, वह सिद्ध नहीं हुआ है, जिससे आरोप को साबित करने के मौलिक सिद्धांत को नजरअंदाज किया गया है, जिसमें दृश्य साक्ष्य और अन्य सहायक साक्ष्यों के बयान को एक साथ लेकर देखा जाना चाहिए।

> *अदालत का कार्य आपराधिक न्याय का प्रशासन करना है, न कि पक्षों द्वारा की गई गलतियों की गिनती करना या यह पता लगाना और घोषित करना कि पक्षों में से किसने बेहतर प्रदर्शन किया।"*

10. अपीलकर्ता के लिए पेश हुए अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निचली अदालत ने सूचनाकर्ता गवाहों, अर्थात् पी.डब्ल्यू.-1, के बयान को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ विशेष आरोप लगाए गए हैं। सभी अन्य गवाहों ने लगातार अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है, लेकिन इसके प्रति पूरी तरह से अनदेखी करते हुए बरी करने का निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार, यह निर्णय विकृतता से ग्रस्त है और कानून की दृष्टि में अस्थिर है, इसलिए इसे रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए और आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A, 365, 386, 379 और 307 के

तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के लिए पेश हुए अधिवक्ता ने बरी करने के निर्णय का बचाव करते हुए प्रस्तुत किया है कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष सही है कि अभियोजन आरोप को संदेह के सभी छायाओं से परे स्थापित करने में असफल रहा है। इस प्रकार, आरोप को साबित करने और अपराधी को दोषी ठहराने के लिए मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि आरोप को संदेह के सभी छायाओं से परे साबित किया जाए। गवाहों के साक्ष्यों को एक साथ लेकर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें व्यापक विरोधाभास है। इसलिए, यदि निचली अदालत ने इन पहलुओं पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन आरोप को संदेह के सभी छायाओं से परे स्थापित करने में असफल रहा है, तो इसे त्रुटि नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, अपीलित बरी करने का निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखता।

12. इस आधार पर प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है और इस तरह इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से पेश प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है, लेकिन बरी किए जाने के विवादित फैसले की वैधता और औचित्य में जाने से पहले, गवाहों की गवाही के बारे में चर्चा करना उचित और उचित समझते हैं।

14. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 6 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें पी. डब्ल्यू. 1 दिनेश सिंह (सूचनार्थी), पी. डब्ल्यू. 2 राजेश कुमार मंडल, पी. डब्ल्यू. 3 चंद्रशेखर सिंह (प्रथम आई. ओ.), पी. डब्ल्यू. 4 अंकिता प्रियदर्शनी (सूचनार्थी की बेटी), पी. डब्ल्यू. 5 कुमारी जूली (सूचनार्थी की पत्नी) और पी. डब्ल्यू. 6 उपेंद्र सिंह (द्वितीय आई. ओ.) शामिल हैं।

15. पी.डब्ल्यू.1 दिनेश सिंह, जो इस मामले के सूचनाकर्ता हैं, ने गवाही दी कि उन्हें मुन्ना तिवारी ने फोन करके बुलाया और कहा कि वह अपने घर विक्रमशिला गढ़ारी टोला पर करीब 12 बजे आएं। जब यह गवाह वहां लगभग 1 बजे पहुंचा, तो वहां पांच से छह लोग पहले से मौजूद थे और उसने चीकू चौधरी, मुन्ना तिवारी, सोनू झा, अनु सिंह और राहुल साह को पहचाना। उन्होंने आगे पैरा-2 में बताया कि अचानक मुन्ना तिवारी ने कहा कि उसने करोड़ों रुपये कहां रखे हैं, तब उसने जवाब दिया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। इसके बाद, सभी आरोपियों ने उठकर उसके गले में गमछा बांध दिया और उसकी गर्दन को दबाया, जिससे वह बेहोश हो गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। जब उसे होश आया, तो उसने पाया कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और सभी आरोपियों ने उस पर हमला किया और पैसे की मांग की। उसने आगे बताया कि लगभग 6 बजे उनके द्वारा उसका मुँह बांध दिया गया और उसे गांव पासना ले जाया गया। मुन्ना तिवारी ने मोबाइल फोन से इस गवाह की पत्नी से बात की और 50,00,000/- रुपये की फिरौती मांगी।

उक्त गवाह ने पैरा-3 और 4 में आगे बताया कि अनुरोध पर आरोपी को गोड्डा लाया गया और वहां से उसे मुक्त किया गया, जहां से वह अपने घर गया और उसके बाद इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने स्वयं सूचनाकर्ता याचिका लिखी, जिसे प्रदर्शित 1 के रूप में चिह्नित किया गया। उसने चीकू चौधरी, सोनू झा, अनु सिंह, और बाबू तिवारी को पहचाना।

16. उसने क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के पैरा 7 में कहा कि अनु सिंह ने उसके खिलाफ गोड्डा टाउन थाना केस नंबर 258/2020 दर्ज किया, लेकिन उसे नहीं पता कि यह मामला चेक बाउंस से संबंधित है, हालांकि उसने अदालत से जमानत ली। पैरा-10 में उसने गवाही दी कि उसने अपनी चिकित्सा के कागजात पुलिस को दिए थे और पैरा-11 में उसने यह भी इनकार किया कि यह सच नहीं है कि वह इलाज नहीं कराता और उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं

हुई, और चोटों की कहानी मनगढ़ंत है।

पैरा-13 में उसने गवाही दी कि एक महीने तक, वह और उसके परिवार के सदस्य कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराए।

17. पी.डब्ल्यू.2 राजेश कुमार मंडल, जो दिनेश सिंह (सूचनाकर्ता) के घर में मजदूर के रूप में काम करते हैं, ने गवाही दी कि 07.08.2019 को सुबह लगभग 7 से 8 बजे वह दिनेश सिंह के शांति नगर स्थित घर में गए। दिनेश सिंह की पत्नी छत पर बैठी थीं और जब उन्होंने काम मांगा, तो उसने उन्हें वापस जाने और अगले दिन आने के लिए कहा। फिर, वह 08.08.2019 को सुबह लगभग 8:30 बजे दिनेश सिंह से छत पर मिले, तब उन्होंने दिनेश सिंह की आंखों और चेहरे पर चोटें देखीं। जब उन्होंने चोटों के बारे में पूछा, तो यह बताया गया कि मुन्ना तिवारी ने उनका अपहरण किया और उन्हें पीटा तथा 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी।

18. क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के पैरा 6 में उसने यह इनकार किया कि वह दिनेश सिंह के साथ यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साझेदार है। पैरा 8 में उसने स्वीकार किया कि अनु सिंह ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और यह भी इनकार किया कि अनु सिंह ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा साहेबगंज में उसके और दिनेश सिंह के संयुक्त खाते में पैसे ट्रांसफर किए। पैरा 11 में, उसने कहा कि उसे दिनेश सिंह के अपहरण के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और उसने यह केवल दिनेश सिंह से सुना है। पैरा 13 में उसने गवाही दी कि एक महीने तक, वह और उसके परिवार के सदस्य कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराए।

19. पी.डब्ल्यू.3 चंद्रशेखर सिंह, गोड्डा टाउन थाना केस संख्या 235/2019 के जांच अधिकारी, ने मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि घटना की तारीख 06.08.2019 थी और उसने 14.09.2019 को जांच का कार्यभार संभाला और संबंधित थाना में दिनेश सिंह का बयान दर्ज किया। उन्होंने आगे गवाही दी कि वह सूचनाकर्ता के साथ घटना स्थल विक्रमशिला लहेरी टोला गए और वहां लगभग 21:45 बजे पहुंचे। फिर 15.09.2019 को सुबह लगभग 8:30 बजे, वह घटना स्थल की ओर बढ़े और वहां लगभग 9:15 बजे पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि घटना स्थल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने बताया कि अशोक तिवारी रात में दोस्तों के साथ यहां रुके थे और इसके पास एक पैतृक घर है, जिसमें उसके भाई, पिता, बहन और पत्नी रहते हैं। उन्होंने पैरा-4 में आगे बताया कि बाद में वह दिनेश सिंह के घर, शांति नगर वार्ड नंबर 15 गए, जहां उन्होंने सूचनाकर्ता की पत्नी कुमारी जूली और सूचनाकर्ता की बेटी अंकिता प्रदर्शनी का बयान दर्ज किया। बाद में, उन्होंने राजेंद्र मंडल का भी बयान दर्ज किया और वहां कोई अन्य स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। उन्होंने पैरा-7 में कहा कि 20.09.2019 को सूचनाकर्ता दिनेश सिंह, उसकी पत्नी जूली और बेटी प्रदर्शनी संबंधित पी.एस. पर आए, जिन्हें धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान के लिए अदालत में पेश किया गया। पैरा-11 में उन्होंने कहा कि 30.12.2019 को वह गोड्डा टाउन से स्थानांतरित हो गए, इसलिए जांच का कार्यभार गोड्डा टाउन के पी.एस. इंचार्ज को सौंप दिया गया और जांच के दौरान उन्होंने किसी भी आरोपी से मुलाकात नहीं की, इसलिए वह किसी को पहचान नहीं सकते।

20. क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के दौरान उसने गवाही दी कि 06.08.2019 को, दिनेश सिंह ने मुन्ना तिवारी को लगभग 10:19 बजे फोन किया और लगभग 59 सेकंड तक बात की। फिर, दिनेश सिंह ने 12:53 बजे मुन्ना तिवारी को फिर से फोन किया और लगभग 11 सेकंड तक बात की, और उस समय सूचनाकर्ता का स्थान मुन्ना तिवारी के घर के पास था। 06.08.2019 को लगभग 13:21 बजे, सूचनाकर्ता और मुन्ना तिवारी का स्थान पत्थरगामा में था और फिर लगभग 14:17 बजे, सूचनाकर्ता और मुन्ना तिवारी दोनों का स्थान विक्रमशिला में था। पैरा-15 में उसने गवाही दी कि जब्त किए गए मोबाइल से घटना से संबंधित कोई संलिप्तता नहीं पाई गई और उसने कभी भी अदालत में वारंट के लिए अनुरोध नहीं किया, और आरोपियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। पैरा-18 में उसने खुलासा किया कि 20.09.2019 तक

स्थानांतरण के समय तक, जांच के दौरान कोई प्रासंगिक साक्ष्य नहीं मिला।

21. पी.डब्ल्यू.4 अंकिता प्रदर्शनी, सूचनाकर्ता की बेटी हैं, जिन्होंने मुख्य परिक्षण में गवाही दी कि 06.08.2019 को लगभग 2 बजे वह शांति नगर, गोड्डा में घर पर थीं, जब उनके पिता को फोन आया और उनके पिता ने बताया कि मुन्ना तिवारी ने उन्हें फोन किया और उनके पिता एक अन्य व्यक्ति के साथ सफेद रंग की गाड़ी में घर से निकल गए। जब उनके पिता रात 12 बजे तक वापस नहीं आए, तो उन्होंने रात 12 बजे मुन्ना तिवारी को फोन किया। आगे उन्होंने पैरा-3 में गवाही दी कि मुन्ना तिवारी ने जवाब दिया कि उसने पता लगाने की कोशिश की और उसके जवाब का इंतजार करते-करते वह रात में सो गई। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपने सभी परिवार के सदस्यों को अपने पिता के बारे में सूचित किया। पैरा-5 में उन्होंने कहा कि सुबह लगभग 6 बजे मुन्ना तिवारी ने उन्हें फोन करके बताया कि आपके पिता का अपहरण कर लिया गया है और 50 लाख रुपये की मांग की है, और जब उन्होंने अपने पिता के बारे में पूछा, तो उसने उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पैरा-6 में उन्होंने कहा कि मुन्ना तिवारी का संपर्क नंबर उनके पिता ने घर छोड़ते समय दिया था। उन्होंने पैरा-7 में कहा कि जब उन्होंने सुना कि उनके पिता का अपहरण हो गया है, तो उन्होंने पिता से बात करने के लिए कहा, फिर कुछ समय बाद मुन्ना तिवारी ने उनके पिता को बात करने के लिए उपलब्ध कराया, तब उनके पिता ने कहा कि मुन्ना तिवारी जो कहे उसे मानें, फिर उन्होंने फोन अपनी मां को दे दिया। हालांकि पैरा-8 में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में अपने चाचा, चाची, दादा, दादी, मामा और मामी को नहीं बताया, बल्कि केवल अपनी मां को बताया, फिर मां ने सभी परिवार के सदस्यों को सूचित किया। पैरा-10 में उन्होंने धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान और अपने हस्ताक्षर की पहचान की। पैरा-11 में उन्होंने खुलासा किया कि इस मामले में आरोपी कौन है, उन्हें नहीं पता।

22. क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के दौरान उसने गवाही दी कि 06.08.2019 को, उसने अभय मैनेजर से ज़ेरॉक्स की दुकान पर मुलाकात की, जब उसके पिता ने उसे अभय मैनेजर से मिलवाया। पैरा-25 में उसने इस सुझाव का खंडन किया कि उसके पिता ने यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते से 05.09.2018 को उसके खाते में 25 लाख रुपये ट्रांसफर किए। पैरा-27 में उसने इस सुझाव का खंडन किया कि वह यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में जानती है। पैरा-31 में उसने स्वीकार किया कि उसके पिता के अपहरण के बाद, चीकू चौधरी उसके घर के पास मौजूद रहे, तब उसके पिता ने उसे उनसे मिलवाया। पैरा-33 में उसने कहा कि घटना के बारे में उसने वही गवाही दी जो उसके पिता ने उसे बताई और उसे व्यक्तिगत रूप से घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

23. पी.डब्ल्यू.5 कुमारी जूली, सूचनाकर्ता की पत्नी, ने मुख्य परीक्षा में पैरा-1 में गवाही दी कि घटना 06.08.2019 को हुई, जब वह स्कूल में थीं और शाम लगभग 4 बजे लौटने पर उनकी बेटी अंकिता ने उन्हें बताया कि उनके पिता मुन्ना तिवारी के साथ गए हैं। उन्होंने आगे पैरा-2 में कहा कि उन्होंने अपने पति को फोन किया लेकिन उनका फोन बंद था। अगले दिन सुबह, उनकी बेटी अंकिता ने उन्हें फोन करके बताया कि मुन्ना तिवारी उन्हें फोन कर रहा है और यह भी बताया कि उनके पिता का अपहरण कर लिया गया है और 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई है। पैरा-3 में उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने मुन्ना तिवारी का फोन प्राप्त किया और पूछा कि दिनेश से बात करने के लिए कहां हैं, तब उन्होंने दिनेश से बात की। 07.08.2019 को मुन्ना तिवारी ने बताया कि दिनेश का अपहरण कर लिया गया है, जब पूछा गया कि किसने अपहरण किया, तो उसने अपहरणकर्ता का नाम नहीं बताया। मुन्ना तिवारी ने केवल यह जानकारी दी कि 50 लाख रुपये देने होंगे तब दिनेश को अपहरण से मुक्त किया जाएगा। गवाह ने पैरा-6 में कहा कि 07.08.2019 को रात लगभग 8 बजे दिनेश उनके घर के बाहर मुक्त पाए गए और जब वह घर के अंदर आए, तो उन्होंने दिनेश की आंखों पर सूजन और हाथों और पैरों पर चोटें देखीं। जब उन्होंने पूछा कि यह कैसे हुआ, तो दिनेश ने नहीं

बताया क्योंकि वह बहुत डरे हुए थे और सो गए। उन्होंने धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे एक्सट.3 के रूप में चिह्नित किया गया। पैरा-9 में गवाह ने केवल दो आरोपियों अमित कुमार तिवारी और सौरव कुमार चौधरी की पहचान की।

24. क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के दौरान पैरा-13 में उसने कहा कि उसे पता है कि मुन्ना तिवारी को इस मामले में पहले ही बरी किया जा चुका है। पैरा-15 में उसने कहा कि उसके पति व्यवसायी थे।

25. पी.डब्ल्यू.6 उपेंद्र सिंह, इस मामले के दूसरे जांच अधिकारी, ने मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि उन्होंने 19.02.2020 को रामाकांत तिवारी से जांच का कार्यभार संभाला। पैरा-4 में उन्होंने कहा कि 30.04.2020 को उन्होंने आरोपी अनु सिंह के खिलाफ धारा 364ए, 365, 386, 379, 307 और 34 आईपीसी के तहत चार्ज शीट संख्या 70/2020 प्रस्तुत की और पूरक जांच जारी रखी। आगे पैरा-9 में उन्होंने कहा कि 08.02.2021 को उन्होंने दो नामित आरोपियों अभय कुमार और पप्पू झा उर्फ राजीव रंजन झा के खिलाफ धारा 364ए, 365, 386, 379, 307/34 आईपीसी के तहत चार्ज शीट संख्या 27/21 प्रस्तुत की। पैरा-10 में, उन्होंने जब्त किए गए मोबाइल के संबंध में एक जब्ती सूची प्रस्तुत की, जिसे सामग्री एक्सट.-I, I/1, I/2, I/3 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

26. क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के दौरान पैरा-12 में उसने कहा कि चोरी की गई गाड़ियां नहीं मिलीं, इसलिए उसने पुलिस अधीक्षक को गजट प्रकाशन के लिए सीआईजी दिया, जो पूरक केस डायरी के पैरा-24 में उल्लेखित है। उसने आगे पैरा-14 में कहा कि जब्ती सूची में पैरा-40 में जब्त किए गए सामानों का उल्लेख है, जिसमें रोलर, एस्कॉर्ट मॉडल नंबर E.C. 5250, इंजन नंबर 4H33281820297 शामिल हैं, जिसे 11.05.2021 की सीआईजी में प्रकाशित किया गया। उसने पैरा-20 में कहा कि उसने जब्ती सूची तैयार नहीं की, बल्कि केवल डायरी में अनुमोदन किया और पैरा-21 में उसने स्वीकार किया कि पूरक डायरी उसकी लिखावट में नहीं है और पूरक केस डायरी दिनांक 15.12.2020 के पैरा-92, 93, 94 और दिनांक 06.12.2020 के पैरा-1, 2, और 3 उसकी लिखावट में नहीं हैं और ऐसे पैराग्राफ किसी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं, जिसका नाम उसे नहीं पता।

27. उसने क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के पैरा-22 में आगे कहा कि केस डायरी दिनांक 08.02.2021 के पैरा-49, 50, 51 और दिनांक 20.02.2021 के पैरा-1, 2, 3, 4 उसकी लिखावट में नहीं हैं और ये पैराग्राफ किसने लिखे हैं, उसे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है। फिर 25.02.2020 के पैरा-119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 भी उसकी लिखावट में नहीं हैं, ये भी किसी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं, जिसका नाम उसे याद नहीं है। पैरा-25 में उसने कहा कि उसने अभय कुमार के खिलाफ चार्ज शीट प्रस्तुत की, जो अदालत में आत्मसमर्पण कर चुका है और घटना के समय गोड्डा बैंक में पोस्टेड था। उसने आगे कहा कि अभय कुमार इस मामले में शामिल नहीं है और पप्पू झा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पैरा-29 में यह भी कहा गया कि उसने जांच के दौरान किसी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया और इस मामले में कोई आंखों का गवाह नहीं है। पैरा-30 में उसने कहा कि उसने अन्य आरोपियों सौरव कुमार चौधरी, चीकू चौधरी, सोनू झा, पप्पू झा और अनु सिंह के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। जांच के दौरान उसे पता चला कि वे मुन्ना तिवारी के साथ रह रहे हैं, इसके बाद उसने इन आरोपियों के खिलाफ चार्ज प्रस्तुत किया लेकिन उसने कभी उन लोगों को मुन्ना तिवारी के साथ नहीं देखा। पैरा-36 में यह भी कहा गया कि यह सच है कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर उसने निर्दोष आरोपियों के खिलाफ झूठी चार्ज शीट प्रस्तुत की और आरोपी गलत जांच के कारण न्यायिक हिरासत में रहे।

28. उपरोक्त गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद और मामले के योग्यता में प्रवेश करने

से पहले, धारा 378 के तहत अपील अदालत की शक्ति और अधिकार क्षेत्र का उल्लेख करना आवश्यक है।

29. एक अपीलीय अदालत के पास बरी करने के आदेश के आधार पर मौजूद साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, और 1973 का दंड प्रक्रिया संहिता ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाता। एक अपीलीय अदालत अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँच सकती है।

30. हालांकि, अपीलीय अदालत को बरी करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने का निर्णय लेने से पहले यह आवश्यक है कि वह एक निष्कर्ष दर्ज करे कि रिकॉर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी के कारण ऐसे मजबूर कारण हैं, जो बरी करने के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

इस संबंध में संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटका राज्य, (2007) 4 एससीसी 415** में दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को निचली अदालत द्वारा दर्ज बरी करने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए। संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जा रहा है:

> *"**42**. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं:*
>
> *(1) एक अपीलीय अदालत के पास बरी करने के आदेश के आधार पर मौजूद साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है।*
>
> *(2) 1973 का दंड प्रक्रिया संहिता ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाता, और एक अपीलीय अदालत अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँच सकती है।*
>
> *(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे "महत्वपूर्ण और मजबूर कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ" आदि, अपीलीय अदालत की बरी करने के खिलाफ अपील में व्यापक शक्तियों को सीमित करने के लिए नहीं हैं। ऐसे वाक्यांश अधिकतर "भाषा की अलंकारिकता" के रूप में हैं, जो अपीलीय अदालत की बरी करने में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा को उजागर करते हैं, न कि अदालत की साक्ष्यों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँचने की शक्ति को सीमित करने के लिए।*
>
> *(4) हालांकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी करने के मामले में, आरोपी के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। पहली, निर्दोषता की धारणा उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत उपलब्ध है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष*

माना जाएगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं किया जाता। दूसरी, आरोपी ने अपनी बरी करने की स्थिति प्राप्त कर ली है, जिससे उसकी निर्दोषता की धारणा और भी मजबूत, पुनः पुष्टि और सुदृढ़ होती है निचली अदालत द्वारा।
(5) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को निचली अदालत द्वारा दर्ज बरी करने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

31. इसी तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2000) 4 एससीसी 484** के मामले में यह पाया कि अपीलीय अदालतों द्वारा बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अनुसरण करने वाला सिद्धांत यह है कि हस्तक्षेप केवल तब किया जाना चाहिए जब "मजबूर और महत्वपूर्ण कारण" हों। यदि आदेश "स्पष्ट रूप से असंगत" है, तो यह हस्तक्षेप का एक मजबूर कारण है। संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जा रहा है:

"21. अपीलीय अदालतों द्वारा बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अनुसरण करने वाला सिद्धांत यह है कि हस्तक्षेप केवल तब किया जाना चाहिए जब "मजबूर और महत्वपूर्ण कारण" हों। यदि आदेश "स्पष्ट रूप से असंगत" है, तो यह हस्तक्षेप का एक मजबूर कारण है (शिवाजी साहाबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य)। इस सिद्धांत को रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य में स्पष्ट किया गया: (एससीसी पृष्ठ 229, पैरा 7) "बरी करने के मामले में निर्णय देते समय, अपीलीय अदालत को पहले इस प्रश्न का उत्तर खोजने की आवश्यकता होती है कि क्या निचली अदालत के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं। यदि अपीलीय अदालत उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देती है, तो बरी करने का आदेश बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि अपीलीय अदालत यह निर्धारित करती है, रिकॉर्ड किए गए कारणों के आधार पर, कि बरी करने का आदेश किसी भी उपरोक्त दोषों के दृष्टिगत किसी भी प्रकार से स्थिर नहीं हो सकता, तो वह तब -- और केवल तब -- साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकती है ताकि अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँच सके।"

32. अब तत्काल मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर आते हुए यह स्पष्ट है कि कथित घटना की प्राथमिकी दर्ज करने में एक महीने से अधिक की देरी हुई थी।

33. हालांकि, यह एक स्थापित सिद्धांत है कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कानून को सक्रिय करना है और अभियोजन पक्ष को हर घंटे की देरी का स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जा सकता। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में केवल देरी पूरी अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती, और ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष पुलिस को सूचित करने में देरी के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

34. हालांकि, जहाँ भी बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया जाता है कि पुलिस को रिपोर्ट दर्ज

कराने में देरी किसी छिपे हुए इरादे के कारण थी या देरी ने सूचनाकर्ता को झूठी कहानी गढ़ने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया, वहाँ अदालत को देरी का स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक है और अभियोजन की कहानी की सत्यता की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।इस मामले में, क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के दौरान, गवाहों ने ऐसे तथ्यों को स्वीकार किया जो पूरी तरह से सूचनाकर्ता के उस बहाने को नकारते हैं कि उसने अपने कथित अपहरण और हत्या के प्रयास के लगभग एक महीने बाद पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

35. यह सूचनाकर्ता पीड़ित की गवाही से स्पष्ट है, जिसे पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षण किया गया है, कि उसकी गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास है, जिसे निचली अदालत द्वारा भी ध्यान में रखा गया है और जिसके आधार पर बरी करने का निर्णय पारित किया गया है।

36. सूचनाकर्ता की गवाही के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना का कोई आंखों का गवाह नहीं था, जब उसे आरोपियों द्वारा पीटा गया और हमले के दौरान रक्त बहा, लेकिन पुलिस को घटना स्थल पर पीटने और रक्त बहने के कोई निशान नहीं मिले। उसने यह भी कहा कि उसे पप्पू झा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसने उसे खाना और पानी दिया था।

37. इसके अलावा, अपीलकर्ता ने केवल मुन्ना तिवारी, चीकू चौधरी, सोनू झा पर आरोप लगाया कि उन्होंने उस पर हमला किया, लेकिन इस गवाह के बयान के समर्थन में कोई चिकित्सा चोट उपलब्ध नहीं है, इसलिए सूचनाकर्ता का बयान स्वतंत्र और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्टि के अभाव में विश्वसनीय नहीं लगता।

38. पी.डब्ल्यू.2 की गवाही को देखते हुए, जहाँ पैरा-11 में उसने गवाही दी कि उसे सूचनाकर्ता के अपहरण के बारे में कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है और उसने घटना के बारे में केवल सूचनाकर्ता से ही सुना। चूंकि यह गवाह आंखों का गवाह नहीं है और उसने आरोपियों के खिलाफ विशेष रूप से कुछ भी आपराधिक नहीं कहा, इसलिए निचली अदालत ने इस गवाह की गवाही पर अधिक भरोसा नहीं किया।

39. पी.डब्ल्यू.3 की गवाही से, जो मामले का पहले जांच अधिकारी है, यह स्पष्ट होता है कि उसने केवल चार मोबाइल और एक एयर गन घटना स्थल से जब्त की थी। हालांकि, उसने गवाही दी कि ये जब्त की गई वस्तुएं आरोपित अपराध में उपयोग नहीं की गई थीं। अपनी गवाही में उसने कहा कि कथित घटना के दिन, अर्थात 06.08.2019 को मुन्ना तिवारी ने सूचनाकर्ता को कॉल नहीं किया, बल्कि सूचनाकर्ता ने स्वयं मुन्ना तिवारी से सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे बात की। इसके अलावा, सूचनाकर्ता और मुन्ना तिवारी दोनों का स्थान पत्थरगामा क्षेत्र में पाया गया और बाद में वे विक्रमशिला घर, गोड्डा लौट आए। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियोजन की कहानी इस गवाह द्वारा समर्थित नहीं है।

40. पी.डब्ल्यू.4, जो सूचनाकर्ता की बेटी है, ने गवाही दी कि उसने कथित घटना के बारे में घर पर मौजूद अन्य परिवार के सदस्यों को सूचित किया, लेकिन रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कोई अन्य परिवार के सदस्य, दादा, दादी, चाचा, चाची निचली अदालत में अभियोजन गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं ताकि कथित घटना को प्रमाणित किया जा सके।

41. पी.डब्ल्यू.5 (सूचनाकर्ता की पत्नी) की मुख्य और क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सूचनाकर्ता (पी.डब्ल्यू.1) ने इस गवाह को अपहरण के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसने अपनी बेटी से सीखा कि मुन्ना तिवारी ने बताया कि उसने उसके पिता का अपहरण कर लिया है। कथित घटना का दिन 06.08.2019 था और मामला 14.09.2019 को दर्ज किया गया, और इस अवधि के दौरान, वह लगातार स्कूल गई, जहाँ वह एक शिक्षक थीं, लेकिन उन्होंने कभी पुलिस या अन्य रिश्तेदारों को घटना के बारे में नहीं बताया। इस प्रकार,

निचली अदालत ने इस गवाह के व्यवहार को असामान्य पाया और इसलिए उसकी गवाही पर अदालत ने भरोसा नहीं किया।

42. उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यदि एक गवाह आरोपी के खिलाफ गंभीर रूप से आरोप लगाने वाली परिस्थिति के बारे में जानने का दावा करता है और वह उस आरोपित परिस्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण अवधि तक चुप रहता है, तो उसका बयान अपनी अधिकांश मूल्य खो देता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जो **(1973) 2 एससीसी 808** में रिपोर्ट किया गया है। प्रासंगिक पैराग्राफ, अर्थात्, पैराग्राफ-14 का अंश निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है:

> *"14. ... यदि एक गवाह हत्या के अपराध के आरोपी के खिलाफ गंभीर रूप से आरोप लगाने वाली परिस्थिति के बारे में जानने का दावा करता है और वह उस आरोपित परिस्थिति के बारे में दो महीने से अधिक समय तक चुप रहता है, तो उसके द्वारा दी गई उस आरोपित परिस्थिति से संबंधित बयान, किसी ठोस कारण के अभाव में, अपनी अधिकांश मूल्य खोने के लिए बाध्य है। ..."*

43. इस मामले में, निचली अदालत ने सूचनाकर्ता की अपहरण की कहानी पर विश्वास नहीं किया, जिसे पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षण किया गया। निचली अदालत ने पाया कि 50 लाख रुपये के फिरौती के लिए अपहरण और यातना के आरोप और सूचनाकर्ता के हाथ, पैर और मुंह बांधने के आरोप को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित नहीं किया गया।

निचली अदालत ने यह भी पाया कि जांच अधिकारी ने कथित घटना में प्रयुक्त रस्सी या गमछा जब्त नहीं किया।

पी.डब्ल्यू.6 के रूप में परीक्षण किए गए जांच अधिकारी उपेंद्र सिंह की गवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने सूचनाकर्ता द्वारा सूचना याचिका में आरोपित चोरी की गाड़ियों की जब्ती सूची तैयार नहीं की या पूछताछ नहीं की। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनाकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ झूठा आरोप लगाया, लेकिन जांच उचित तरीके से नहीं की गई।

44. इस अदालत ने तथ्यात्मक पहलू को कानूनी स्थिति के साथ चर्चा करने के बाद, निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की गहन जांच की और पाया कि पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.4, पी.डब्ल्यू.5, पी.डब्ल्यू.6 और अन्य गवाहों की गवाहियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई है। इसके परिणामस्वरूप, निचली अदालत ने यह नहीं पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह के सभी साए से परे साबित करने में सक्षम रहा है, और इस मामले के दृष्टिकोण से, बरी करने का निर्णय पारित किया गया है।

45. कानून की स्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित है कि यदि अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह के सभी साए से परे साबित करने में असमर्थ है, तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने के लिए उसकी सजा नहीं हो सकती, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रंग बहादुर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में **(2000) 3 एससीसी 454** में कहा है, जहाँ पैरा 22 में यह कहा गया है:

> *"22. इस मामले में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में अदालत द्वारा रखे जाने वाले संदेह का स्तर उचित संदेह के स्तर से कहीं अधिक है। हम जानते हैं कि इस प्रकार के मामले में आरोपी को बरी करना सभी संबंधित लोगों के लिए संतोष का विषय नहीं है। साथ ही,*

हम उस समय-परीक्षित नियम को याद करते हैं कि एक दोषी व्यक्ति की बरी करना एक निर्दोष व्यक्ति की सजा देने से बेहतर होना चाहिए। जब तक अभियोजन पक्ष आरोपी की दोषिता को उचित संदेह से परे साबित नहीं करता, तब तक आरोपी पर सजा नहीं दी जा सकती। एक आपराधिक अदालत अपीलकर्ताओं की स्वतंत्रता, जीवनभर की स्वतंत्रता, को इस बिना वंचित नहीं कर सकती कि उसे कम से कम यह सुनिश्चित करने का उचित स्तर न हो कि अपीलकर्ता वास्तव में अपराधी थे। हम वास्तव में अपीलकर्ताओं की अपराध में संलिप्तता के बारे में संदेह रखते हैं।"

इसके अलावा, **शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और अन्य** मामले में, जो **(2018) 7 एससीसी 581** में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 28 में यह कहा है जो निम्नलिखित है:

"28. इस मामले में, धोखेबाज़ को संबंधित अधिकारी द्वारा नहीं पाया गया या उसकी जांच नहीं की गई। धोखेबाज़ और प्रतिवादी 1 के बीच के संबंध के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून इस तथ्य के संबंध में स्पष्ट है कि चाहे संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। मजबूत संदेह, संयोग, गंभीर संदेह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकते। अदालतों पर हमेशा यह कर्तव्य होता है कि वे सुनिश्चित करें कि संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान न ले। इस मामले में, निचली अदालत और अपीलीय अदालत दोनों इस तथ्य से प्रभावित हो गईं कि आरोपी बंधक दस्तावेज का लाभार्थी या कार्यान्वयनकर्ता है, जबकि अभियोजन पक्ष पहले लेन-देन यानी पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) को धोखाधड़ी और जाली लेन-देन के रूप में साबित करने में बुरी तरह से असफल रहा। एक आपराधिक परीक्षण में प्रमाण का मानक उचित संदेह से परे होता है क्योंकि किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी संभाव्यता के प्रबलता के मानक द्वारा नहीं छीना जा सकता।"

46. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दोषमुक्ति अपील संख्या 18/2022, जो अशोक तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की बरी करने के खिलाफ दायर की गई थी, जिसे घटना का मुख्य आरोपी माना गया था, पहले ही इस अदालत की समकक्ष पीठ द्वारा खारिज कर दी गई है।

47. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से हमें पता चलता है कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों और निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों पर बारीकी से चर्चा की है, जो ठोस कारण हैं और कानून के अनुसार हैं।

48. इसलिए, उपरोक्त चर्चा के आधार पर और ऊपर उल्लेखित स्थापित कानूनी सिद्धांत के प्रकाश में, हमें निचली अदालत द्वारा पारित विवादित निर्णय में कोई स्पष्ट या अंतर्निहित अवैधता और/या अनियमितता नहीं मिलती है, जिसमें आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364ए, 365, 386, 379 और 307 के तहत बरी किया गया है, जिसे इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप योग्य नहीं माना गया।

49. परिणामस्वरूप, अपील को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाता है।

50. इस आदेश की प्रति के साथ निचली अदालत के अभिलेख को संबंधित अदालत को तुरंत वापस भेजा जाए।

51. चूँकि इस अदालत ने अंतिम खारिज आदेश पारित करने के बाद बरी करने के निर्णय में कोई दोष नहीं पाया है, इसलिए अब हम निचली अदालत द्वारा दिए गए अवलोकनों की जांच करने जा रहे हैं, जो विवादित आदेश में उपलब्ध हैं और जिन्हें यहाँ निम्नलिखित रूप में संदर्भित किया जा रहा है:

> *"रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जांच अधिकारी पी.डब्ल्यू.6 उपेंद्र सिंह ने अपनी क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन के पैरा-21 और 22 में स्वीकार किया कि उन्होंने 15.12.2020, 06.12.2020, 08.02.2021, 20.02.2021 और 25.02.2020 को स्वयं अनुपूरक केस डायरी नहीं लिखी, जो एक सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम उन्हें नहीं पता। उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उचित जांच पर ध्यान नहीं दिया और एफ.आई.आर. में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एस.डी.पी.ओ., गोड्डा और एस.पी., गोड्डा ने चार्जशीट प्रस्तुत करने के लिए पर्यवेक्षी नोट जारी किया, जबकि केस डायरी में कोई प्रासंगिक मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। इसलिए, ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है, जो समाज के निर्दोष व्यक्तियों को परेशान और शोषण करते हैं। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अवैध गतिविधियों में शामिल थे और इस मामले में सूचनाकर्ता दिनेश सिंह, पुत्र पुणेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी मौजा- शांतिनगर, थाना गोड्डा टाउन, जिला गोड्डा के कुछ अपराधियों के साथ सहयोग कर रहे थे। ये वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं, जिन्हें भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य का जिम्मा नहीं दिया जाना चाहिए। ओ/सी को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश की एक प्रति झारखंड के डीजीपी और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को भेजें ताकि उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके, जिन्होंने मामले की उचित जांच नहीं की और निर्दोष आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की, जो बिना किसी गलती के न्यायिक हिरासत में रहे।"*

52. इस न्यायालय ने एक प्रश्न रखा है कि क्या विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित निर्देश के अनुसार गलती करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की गई है, जिन्हें तत्काल मामले से संबंधित जांच करने का कर्तव्य सौंपा गया था।

53. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि चूंकि विवादित फैसले की पुष्टि हो गई है, इसलिए अब राज्य दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्देश पर कार्रवाई करेगा।

54. तदनुसार, राज्य को दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित निर्देश को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने दें।

(श्री सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायधीश)
(श्री नवनीत कुमार, न्यायधीश)

सौरभ
ए.एफ.आर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|